



# BACKGROUNDERS

Press Information Bureau  
Government of India

## वैश्विक स्वास्थ्य शक्ति के रूप में भारत का रूपांतरण

मार्च 1, 2026

### मुख्य बिंदु

- सार्वभौमिक कवरेज- आयुष्मान भारत बीमा, 184,000 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 863 मिलियन डिजिटल स्वास्थ्य आईडी के ज़रिए करोड़ों लोगों को मुफ्त/रियायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है।
- विश्व की फार्मसी- भारत वैश्विक जेनेरिक दवाओं का 20% और यूनिसेफ के टीकों का 55-60% आपूर्ति करता है और 2030 तक इसकी जैव-अर्थव्यवस्था 300 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की ओर अग्रसर है।
- प्रौद्योगिकी और नवाचार- एआई निदान, ड्रोन डिलीवरी और स्वदेशी टीके सबसे दुर्गम आबादी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में सहायक हैं।

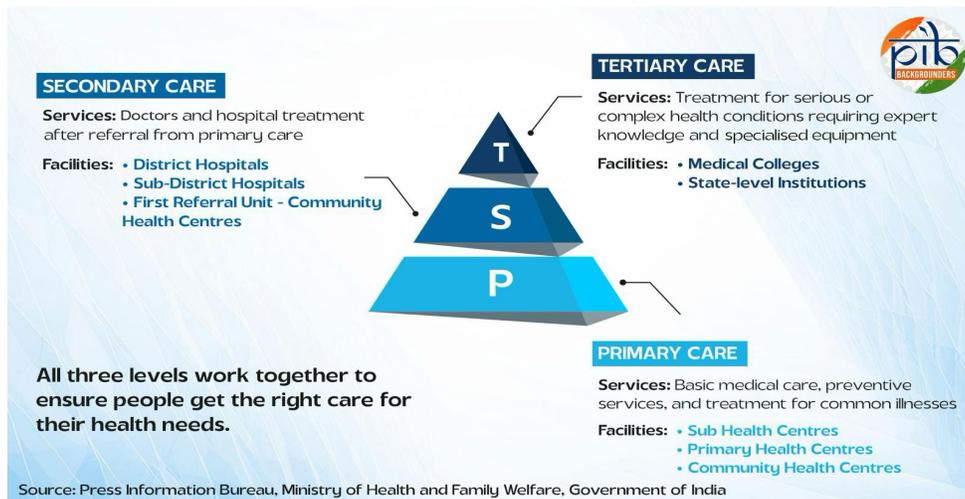
### प्रस्तावना

सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी दीर्घकालिक चुनौतियों पर जीत हासिल करने से लेकर किफायती दवाओं और वैश्विक स्वास्थ्य सेवा वितरण में अग्रणी बनने तक, भारत का वैश्विक स्वास्थ्य शक्ति के रूप में उदय दूरदर्शी नेतृत्व, सुदृढ़ संस्थानों और स्वस्थ, मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा, सभी स्तरों पर मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं और रियायती दवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ व्यापक और सुलभ स्वास्थ्य अवसंरचना प्रदान करने वाली प्रमुख योजनाएं चलाती है। मार्गदर्शक सिद्धांत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है और यह सुनिश्चित करना है कि सबसे सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित आबादी सहित सभी को किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्राप्त हो, ताकि भारत 2047 तक एक स्वस्थ, उत्पादक और समृद्ध समाज, एक विकसित भारत बनने के अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ सके।

भारत की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली, जिसमें निजी कॉलेजों के साथ-साथ सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित संस्थान भी शामिल हैं, ने वर्षों से विस्तार और विकास देखा है। भारत का दवा क्षेत्र, जो मात्रा के हिसाब से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, न केवल भारतीय नागरिकों बल्कि विश्व को भी सस्ती दवाओं की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जैसा कि कोविड-19 टीकों के निर्माण और आपूर्ति में भारत की दक्षता से साफ होता है। भारत का जैव-औषधीय क्षेत्र सरकारी निवेश और निजी उद्योग की नवोन्मेषी भावना की मदद से तेजी से बढ़ रहा है। भारत में चिकित्सा पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, जो 2009 में 112,000 से बढ़कर 2024 में 600,000 से अधिक हो गई है। भारत के चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2026-27 में निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में निदान अवसंरचना और पुनर्वास सेवाओं से लैस पांच एकीकृत चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है। भारत अब वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य में अधिक महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है। यह उस देश के लिए एक यादगार उपलब्धि है, जो एक सदी पहले तक स्थानिक रोगों से जूझ रहा था।

## सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना: आयुष्मान भारत

भारत सरकार की प्रमुख योजना, आयुष्मान भारत (भारत अमर रहे), भारतीय समाज के सभी लोगों, खासकर सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर वर्गों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के अपने लक्ष्य की कुंजी है। इस व्यापक योजना के विभिन्न घटक मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त हों।



इसके चार प्रमुख घटक हैं:

(i) **एबी-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई)**, जो विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है।

(ii) **आयुष्मान आरोग्य मंदिर**, जो उप-स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन के लिए है।

(iii) **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)** - देश भर में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना।

(iv) **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)**, जो नागरिक केंद्रित अंतरसंचालनीय डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था तंत्र की रीढ़ है।

### **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य कार्यक्रम)**

भारत सरकार ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 23 सितंबर, 2018 को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) शुरू की। यह विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा योजना है, जिसमें करोड़ों कमजोर भारतीय परिवार नामांकित हैं।

एबी-पीएमजेएवाई योजना के तहत नामांकित सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित परिवारों और 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं और अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये (लगभग 5,000 अमेरिकी डॉलर) तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें भारी चिकित्सा बिलों से बचाया जा सके। यह योजना सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार प्रदान करती है। इस योजना का लक्ष्य भारतीय आबादी के सबसे निचले 40% हिस्से को लक्षित करना है, जिसमें 120 मिलियन लोग शामिल हैं और अब तक 434 मिलियन से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

## AB-JAY COVERAGE



Over **434 million people** have **Ayushman cards** and are covered under the Ayushman Bharat PM-JAY health assurance scheme. About **967,300 senior citizens** of all classes also enrolled.



The insurance scheme covered **over 106.12 million authorised hospital admissions** across over **36,000 empanelled hospitals**.

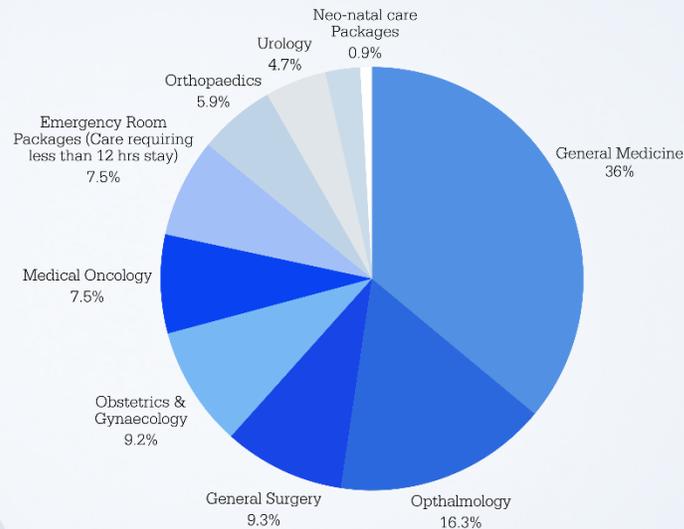


The scheme has **authorised healthcare services valued at over Rs. 234.30 Crores (approx. \$25.74 million USD)** across a wide range of specialties.

As on February 27, 2026

## Hospital Admissions Under AB-PMJAY

There were about 14 million hospital admissions authorised under the scheme across top 10 specialties.



As of February 27, 2026

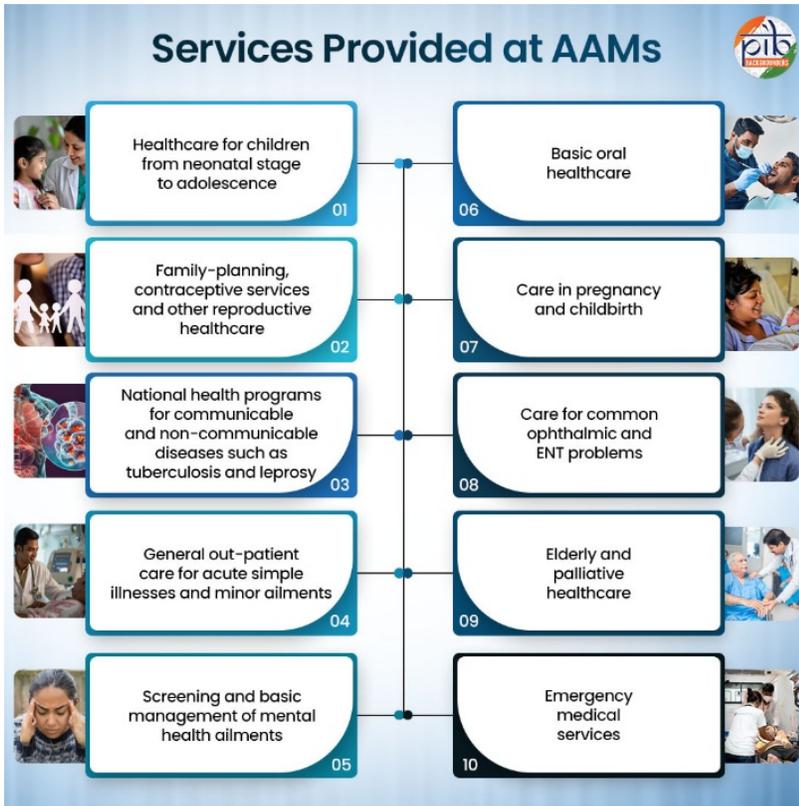
इस योजना ने स्वास्थ्य बीमा पर सरकारी खर्च बढ़ाकर परिवारों के स्वास्थ्य देखभाल खर्च को कम करने में मदद की है। परिवारों को 2024-2025 में 1.25 लाख करोड़ रुपये (लगभग 13.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक की बचत हुई।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आवंटन को बजट अनुमान 2026-27 में बढ़ाकर 9,500 करोड़ रुपये (लगभग 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर) कर दिया गया है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 500 करोड़ रुपये (लगभग 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर) या 5.56% अधिक है। इस वृद्धि का उद्देश्य लाभार्थियों के दायरे को बढ़ाना, सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना और अस्पताल नेटवर्क को मजबूत करना है।

जहां एबी-पीएमजेएवाई माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल का समर्थन करती है, वहीं आयुष्मान भारत योजना गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और एक मजबूत स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अन्य कार्यक्रम चलाती है, जो सभी के लिए सुलभ हो।

## आयुष्मान आरोग्य मंदिर

एक मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना स्वास्थ्य समानता और सुलभता प्रदान करती है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र हैं, जो लोगों को उनके घरों के पास ही व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं।



देश भर में 1,84,235 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं (27 फरवरी, 2026 तक), जिनमें शहरी, ग्रामीण और जनजातीय बहुल क्षेत्र शामिल हैं। 26 राज्यों के 178 जनजातीय जिलों में 30,817 आरोग्य मंदिर और 27 राज्यों के 112 आकांक्षी जिलों में 24,327 आरोग्य मंदिर हैं (31 दिसंबर, 2025 तक)।

स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच करने के लिए, आरोग्य मंदिरों में टेली-परामर्श की सुविधा भी

उपलब्ध है। पिछले वर्ष (31 दिसंबर, 2025 तक) 426.6 मिलियन परामर्श आयोजित किए गए। एएएम वे केंद्र हैं, जहां समुदाय निवारक और संवर्धक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त कर सकता है। लोगों के समग्र विकास के लिए एएएम में योग सहित 58 मिलियन से अधिक स्वास्थ्य सत्र आयोजित किए गए। मंत्रालय राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लाखों लोगों की विभिन्न गैर-संचारी रोगों के लिए जांच करता है। 31 अक्टूबर, 2025 तक, विभिन्न बीमारियों के लिए की गई जांचों की संख्या इस प्रकार है:

- उच्च रक्तचाप की जांच: 401.3 मिलियन
- मधुमेह की जांच: 398.6 मिलियन
- मुख कैंसर की जांच: 338.3 मिलियन
- स्तन कैंसर की जांच: 158.6 मिलियन

### **प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन**

महामारियों या अन्य बीमारियों के प्रकोप के प्रभाव को कम करने और नियंत्रित करने में सामान्य चिकित्सा संस्थानों (एएएम) की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, भारत सरकार ने 2021 में प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) की शुरुआत की। पीएम- एबीएचआईएम स्वास्थ्य, अनुसंधान और निगरानी में अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करता है।

पीएम- एबीएचआईएम का उद्देश्य प्रत्येक जिले में निम्नलिखित की स्थापना और उन्नयन के माध्यम से जमीनी स्तर से लेकर जिला स्तर तक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना है:

- आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम)
- ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयाँ
- एकीकृत जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ
- गहन चिकित्सा अस्पताल ब्लॉक

पीएम- एबीएचआईएम महामारी और आपदा की तैयारियों को भी प्राथमिकता देता है, जिसके लिए ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोगशालाओं को एकीकृत करने वाले एक आईटी-सक्षम,

वास्तविक समय रोग निगरानी नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है, ताकि प्रकोपों का प्रभावी ढंग से पता लगाया जा सके, उनकी जांच की जा सके और उन्हें रोका जा सके।

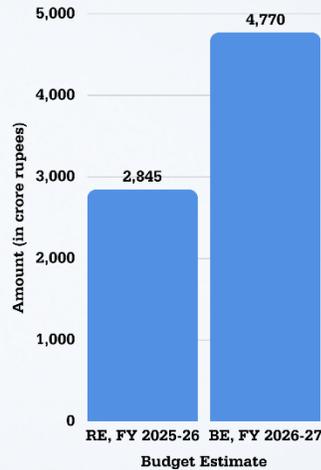
भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 32,928.82 करोड़ रुपये (लगभग 3.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की राशि स्वीकृत की है। यह निधि निम्नलिखित के निर्माण, उन्नयन और स्थापना के लिए है:

- 9,519 भवन रहित उप स्वास्थ्य केंद्र - आयुष्मान आरोग्य मंदिर
- 5,456 शहरी आरोग्य मंदिर
- 2,151 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयाँ
- 744 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ
- जिला अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 622 गहन चिकित्सा ब्लॉक

	March 2020	2025
Testing Labs	14	3400
Domestic Manufacturing capacity of PPE kits	0	4.5 lakh per day
ICU Beds	2,168	1.45 lakh (as of Nov 2023)
Oxygen-supported beds	50,583	5.15 lakh (as of Nov 2023)

## PM-ABHIM Budget Allocation Surge

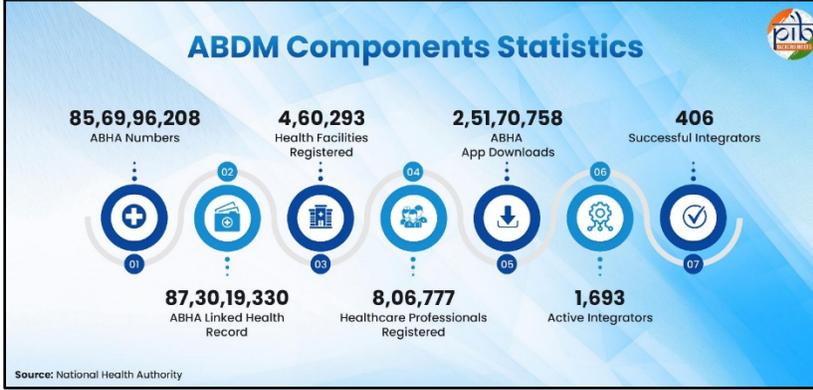
The allocation under PM-ABHIM has seen a **significant jump of 67.66%**, or Rs. 1,925 crore (~USD 212 million), rising from Rs. 2,845 crore (~USD 313 million) in Revised Estimates FY 2025-26 to Rs. 4,770 crore (~USD 526 million) in Budget Estimates FY 2026-27 — reflecting the government's strong commitment to expanding critical health infrastructure across India.



As of February 22, 2026

## डिजिटल पहल - आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और प्रौद्योगिकी एकीकरण

आयुष्मान भारत विश्व की सबसे महत्वाकांक्षी डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों में से एक, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) ज़रिए एक सशक्त डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करता है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (आभा) प्रणाली के तहत लाभार्थियों को एक विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान संख्या आवंटित की जाती है, जिससे उनके चिकित्सा रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है और "डिजिटल स्वास्थ्य लॉकर" के ज़रिए ऑनलाइन देखा जा सकता है।



27 फरवरी, 2026 तक 863 मिलियन से अधिक आभा बनाए जा चुके हैं। एक ऐप के माध्यम से, उपयोगकर्ता पंजीकृत स्वास्थ्य पेशेवरों से भी जुड़ सकते हैं। सत्यापित स्वास्थ्य पेशेवर टेलीकंसल्टेशन के ज़रिए दूर से ही रोगियों का इलाज कर

सकते हैं और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड की समीक्षा कर सकते हैं। यह डिजिटल व्यवस्था अंतिम छोर तक स्वास्थ्य कवरेज को सक्षम बनाती है।

भारत विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य पहलों में से एक का संचालन करता है, जो सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 53 केंद्रों के ज़रिए 20 भाषाओं में 24x7 परामर्श सेवाएं प्रदान करता है और 3.28 मिलियन से अधिक लोगों की मदद कर चुका है। 10 अक्टूबर, 2022 को शुरू की गई टेलीमानस ने 12 भाषाओं में सहायता प्रदान करके अपनी पहुंच का विस्तार किया है और सामान्य स्वास्थ्य से लेकर मानसिक विकारों के प्रबंधन तक व्यापक मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करती है।

## स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव: ड्रोन आधारित चिकित्सा सेवाएं



ड्रोन का उपयोग करके पायलट परियोजनाएं चल रही हैं। 2021 में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीयू) ने मणिपुर और नागालैंड के पहाड़ी राज्यों के दुर्गम क्षेत्रों में टीकों और चिकित्सा सामग्री की ड्रोन आधारित डिलीवरी का परीक्षण करने के लिए 'आई-ड्रोन' पहल शुरू की। विभिन्न भूभागों में सफल पायलट परियोजनाओं के

बाद, कार्यक्रम का विस्तार पूरे देश में विशेष अनुप्रयोगों के साथ किया गया: हिमाचल प्रदेश में उच्च ऊंचाई पर चिकित्सा आपूर्ति (10,000 फीट से ऊपर), तेलंगाना में निदान समय को कम करने के लिए टीबी के नमूनों का परिवहन, कर्नाटक में समय को लेकर संवेदनशील मामलों के लिए पैथोलॉजिकल नमूनों का स्थानांतरण और दिल्ली एनसीआर में रक्त उत्पाद परिवहन अध्ययन। ये

पहलें दर्शाती हैं कि कैसे ड्रोन अंतिम मील स्वास्थ्य सेवा संपर्क को मजबूत कर सकते हैं, निदान में तेजी ला सकते हैं और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में अहम चिकित्सा लॉजिस्टिक्स सहायता प्रदान कर सकते हैं।

## राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

आयुष्मान भारत योजना के अलावा, भारत सरकार दशकों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चला रही है, जिसके दो घटक हैं - राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों की रोकथाम, नियंत्रण और उपचार के लिए काम करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने मानव संसाधनों के विस्तार, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों के समाधान और स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए एकीकृत प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों के माध्यम से भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

एनएचएम टीकाकरण सहित विभिन्न कार्यक्रमों के ज़रिए मातृ, शिशु और किशोर स्वास्थ्य में सुधार लाने, गुणवत्ता मानकों में सुधार करके स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों (एनसीडी) के नियंत्रण कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रबंधन करने का कार्य करता है।

## सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) सबसे बड़े जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है, जिसका लक्ष्य प्रतिवर्ष लगभग 26.7 मिलियन नवजात शिशुओं और 29 मिलियन गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क टीकाकरण प्रदान करना है।

टीकाकरण कवरेज में सुधार के लिए जागरूकता अभियान, सामाजिक जागरूकता, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा पारिवारिक स्तर पर व्यक्तिगत संचार और मीडिया सहभागिता जैसे रणनीतिक हस्तक्षेपों का उपयोग किया जाता है। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सहायक नर्स मिडवाइफ कहलाने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने देश भर में 13 मिलियन से अधिक टीकाकरण सत्र आयोजित किए हैं। देश भर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएचएम) के तहत 1.03 मिलियन से अधिक आशा कार्यकर्ता (एएसएचए) कार्यरत हैं (4 अप्रैल, 2025 तक)।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिए जाने वाले 11 टीके निम्नलिखित हैं:

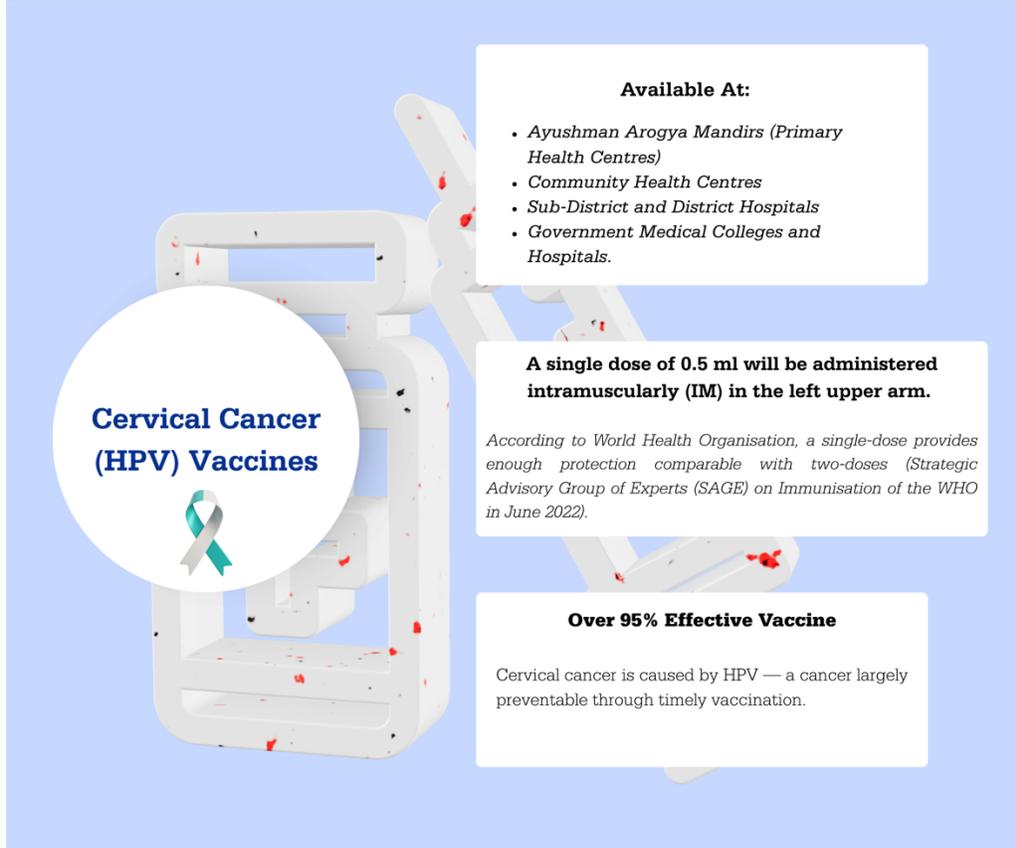
- हेपेटाइटिस बी का टीका
- ओरल पोलियो का टीका (ओपीवी)
- बेसिलस कैलमेट-गुएरिन का टीका (बीसीजी)
- इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला पोलियो का टीका (आईपीवी)
- पेंटावैलेंट टीका
- रोटावायरस का टीका (आरवीवी)
- न्यूमोकोकल कंजुगेट का टीका (पीसीवी)
- खसरा और रूबेला का टीका (एमआर)
- डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस का टीका (डीपीटी)
- टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया का टीका (टीडी) और
- जापानी एन्सेफलाइटिस का टीका (जेई)

### एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया

भारत सरकार ने महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम के लिए 28 फरवरी, 2026 को तीन महीने का राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। गार्डसिल-4 टीका, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा पूर्व-मान्यता प्राप्त एक खुराक वाला टीका है और जिसका उपयोग दुनिया भर के टीकाकरण कार्यक्रमों में किया जाता है, अब केंद्र-राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के सहयोग से देश भर के सभी सरकारी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला और उप-जिला अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 14 वर्ष की किशोरियों को मुफ्त दिया जा रहा है। गार्डसिल-4, एक क्वाड्रिवैलेंट एचपीवी टीका है, जो एचपीवी टाइप 16 और 18 (जो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का कारण बनते हैं) के साथ-साथ टाइप 6 और 11 से भी सुरक्षा प्रदान करता है।

लगभग 11.5 मिलियन किशोरियां वर्तमान में इस टीके के लिए पात्र हैं। अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 90 दिनों का टीकाकरण अभियान प्रतिदिन चलाया जा रहा है और इसके

बाद नियमित टीकाकरण दिवसों पर भी यह उपलब्ध रहेगा। यह राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान भारत की महिलाओं को सशक्त बनाने और देश भर में माताओं और बेटियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस ऐतिहासिक अभियान के साथ, भारत एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम चलाने वाले 160 से अधिक देशों में शामिल हो गया है।



**Cervical Cancer (HPV) Vaccines**

**Available At:**

- Ayushman Arogya Mandirs (Primary Health Centres)
- Community Health Centres
- Sub-District and District Hospitals
- Government Medical Colleges and Hospitals.

**A single dose of 0.5 ml will be administered intramuscularly (IM) in the left upper arm.**

*According to World Health Organisation, a single-dose provides enough protection comparable with two-doses (Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunisation of the WHO in June 2022).*

**Over 95% Effective Vaccine**

Cervical cancer is caused by HPV — a cancer largely preventable through timely vaccination.

## इंद्रधनुष मिशन

25 दिसंबर 2014 को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के तहत इंद्रधनुष मिशन शुरू किया गया था, जिसका मकसद उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना था, जो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से चूक गए थे या बीच में ही टीकाकरण छोड़ चुके थे। इसमें विशेष रूप से कम टीकाकरण कवरेज वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

देश भर में निरंतर, सतत् प्रयासों और टीकाकरण अभियानों के गहन कार्यान्वयन के नतीजतन, कुल जनसंख्या में शून्य खुराक वाले बच्चों का प्रतिशत 2023 में 0.11% से घटकर 2024 में 0.06% हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के टीकाकरण आंकड़ों पर नवीनतम जानकारी।

## अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम, अवसंरचना और प्रभाव

टीकाकरण कार्यक्रम के अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सभी प्रकार की बीमारियों और स्वास्थ्य स्थितियों के लिए कार्यक्रमों का एक व्यापक नेटवर्क चलाता है।

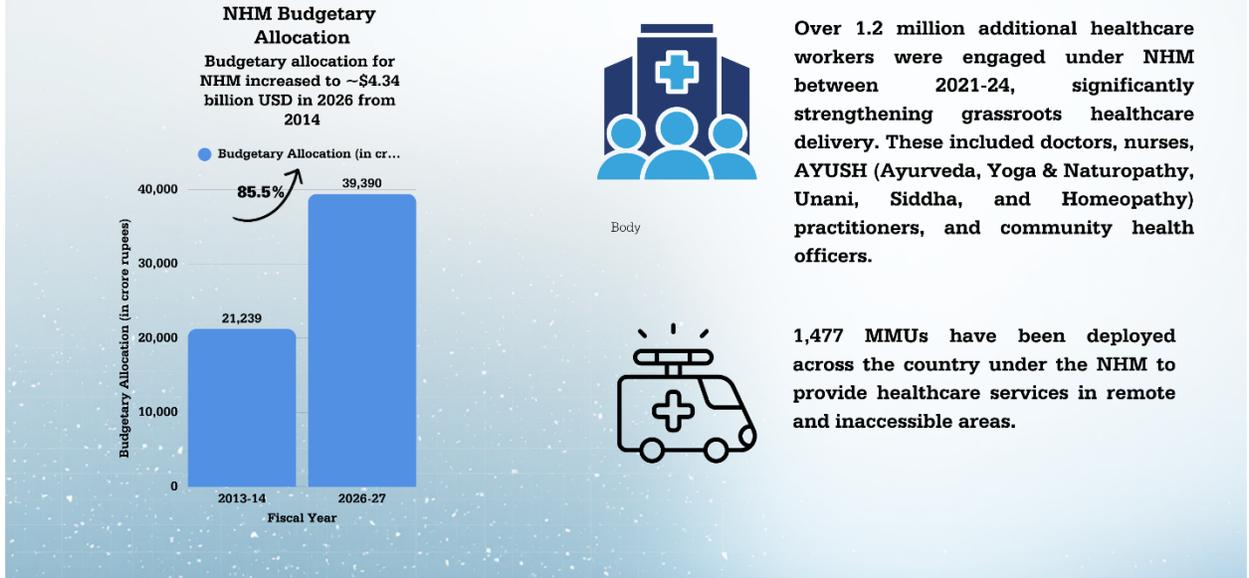
### National Health Mission Components

 RMNCAH+N	 National Missions: Non-Communicable Diseases	 Programmes: Communicable Diseases	 Strengthening Health Systems & Infrastructure
<p><b>Reproductive, Maternal, Newborn, Child, Adolescent Health and Nutrition</b></p> <p>Improving the maternal and child health and their survival are central to the achievement of national health goals under the NHM.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prevention &amp; Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases &amp; Stroke</li><li>• Control of Blindness &amp; Visual Impairment</li><li>• Mental Health Programme</li><li>• Healthcare of Elderly</li><li>• Prevention &amp; Control of Deafness</li><li>• Tobacco Control Programme</li><li>• Oral Health Programme</li><li>• Palliative Care</li><li>• Prevention &amp; Management of Burn Injuries</li><li>• Others</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vector Borne Disease Control</li><li>• Tuberculosis Control</li><li>• Leprosy Eradication</li><li>• Integrated Disease Surveillance</li></ul>	<p>NHM funds infrastructure maintenance.</p> <p>The Mission improves standards by adopting IPHS norms, defining clinical protocols, training health workers through standardized packages, and empowering Hospital Management Societies (RKS) with untied funds — while also supporting quality certification programmes</p>

### बजट में वृद्धि

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के लिए निधि और क्षमता निर्माण में वृद्धि के नतीजतन पिछले कुछ दशकों में भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हुआ है।

## NHM Budget and Infrastructure



### राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- **कोविड-19:** देशभर में 2.2 बिलियन से अधिक टीके लगाए गए।
- **मातृ स्वास्थ्य:** 1990 से मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है, जो वैश्विक स्तर पर 45% की कमी से कहीं अधिक है।
- **बाल स्वास्थ्य:** 1990 से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 75% की कमी आई है, जो वैश्विक स्तर पर 60% की कमी से अधिक है।
- **तपेदिक:** टीबी की घटना दर 2015 में प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 237 से घटकर 2023 में 195 हो गई। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 156,000 निक्षय मित्र स्वयंसेवकों द्वारा 940,000 से अधिक टीबी रोगियों को सहायता प्रदान की गई।
- **खसरा-रूबेला:** गहन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) 5.0 के अंतर्गत 97.98% टीकाकरण कवरेज प्राप्त किया गया, 347.7 मिलियन से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया गया।
- **सिकल सेल एनीमिया:** राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में 26.1 मिलियन से अधिक व्यक्तियों की जांच की गई।

- **डायलिसिस:** इस योजना के अंतर्गत 220,000 से अधिक रोगियों ने डायलिसिस सेवाओं का लाभ उठाया है और 2.5 मिलियन से अधिक हेमोडायलिसिस सत्र आयोजित किए गए हैं (30 जून, 2024 तक)।

- **तंबाकू नियंत्रण:** पिछले एक दशक में तंबाकू के उपयोग में 17.3% की कमी आई है।

## स्वास्थ्य सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण

2022 से 2025 तक, भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को एक एकीकृत रणनीति में शामिल करके अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का मौलिक पुनर्गठन किया है। यह रणनीति विशेषज्ञों की कमी को दूर करती है और सक्रिय देखभाल को व्यापक स्तर पर विस्तारित करती है। फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन के दौरान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में एआई रणनीति (सही) का शुभारंभ किया। ऐसा करने वाला भारत दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र का पहला देश है। यह रणनीति स्वास्थ्य सेवाओं में एआई के अनुप्रयोग में नवाचार और तीव्र वृद्धि को प्रोत्साहित करती है, साथ ही नैतिक उपयोग और आचरण पर जोर देती है। भारत सरकार ने पहले ही एआई को अपने एबीडीएम बुनियादी ढांचे और अन्य कार्यक्रमों में एकीकृत कर लिया है।

भारत में विभिन्न रोग क्षेत्रों और स्वास्थ्य प्रणाली कार्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

- एका डॉक, एक क्लिनिक प्रबंधन प्रणाली, एक एबीडीएम-सक्षम एप्लिकेशन है, जो डॉक्टरों के लिए रोगी रिकॉर्ड की छँटाई, प्रोटोकॉल खोज और सारांश तैयार करने में मदद करती है। इसने दस लाख से अधिक रोगियों की छँटाई की है और 17 लाख से अधिक रिकॉर्ड का सारांश तैयार किया है।
- ईक्लिनिकलवर्क्स द्वारा विकसित सुनो.एआई एक एआई-संचालित लेखन उपकरण है, जो डॉक्टरों को ध्वनि तकनीक का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक नुस्खे बनाने में सक्षम बनाता है, जिससे लाखों ई-नुस्खे तैयार किए जा सकते हैं।
- तपेदिक प्रबंधन में, एक प्रतिकूल परिणाम भविष्यवाणी उपकरण उपचार शुरू होने के समय उपचार विफलता के उच्च जोखिम वाले रोगियों को चिह्नित करने के लिए भविष्यसूचक विश्लेषण का उपयोग करता है और देशव्यापी तैनाती के बाद प्रतिकूल परिणामों में 27% की कमी दर्ज की गई है।

- मधुमेह से संबंधित नेत्र देखभाल के लिए, मधुनेत्रएआई गैर-विशेषज्ञों को रेटिना की तस्वीरें लेने में सक्षम बनाता है, जिन्हें एआई द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, ताकि तत्काल विशेषज्ञ रेफरल को प्राथमिकता दी जा सके। दिसंबर 2025 में भारत के पहले एआई-आधारित सामुदायिक स्क्रीनिंग कार्यक्रम के रूप में शुरू किए गए इस कार्यक्रम से 38 केंद्रों में 7,100 मरीजों को लाभ मिला है।

## दवाओं को किफायती बनाना

स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के अलावा, भारत सरकार प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं किफायती दामों पर उपलब्ध कराती है। ये दवाएं देशभर में स्थित 17,990 जनऔषधि केंद्रों पर उपलब्ध हैं। इन केंद्रों पर 2,000 से अधिक दवाएं और 315 शल्य चिकित्सा उत्पाद उपलब्ध हैं, जो बाजार मूल्य से 50-90% कम दरों पर बेचे जाते हैं। ये दवाएं हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह और अन्य कई बीमारियों के इलाज में सहायक हैं। इस योजना से लाभार्थियों को पिछले दशक में लगभग 30,000 करोड़ रुपये (लगभग 3.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की बचत हुई है।

पीएमबीजेपी के पूरक के रूप में, सरकार ने किफायती दवाएं और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) पहल शुरू की, जिसका मकसद विशेष रूप से तृतीयक स्वास्थ्य सेवा को सहायता प्रदान करना है। अमृत फार्मेशियां ब्रांडेड, ब्रांडेड-जेनेरिक और जेनेरिक दवाओं के साथ-साथ शल्य चिकित्सा सामग्री, उपभोग्य वस्तुएं और चिकित्सा प्रत्यारोपण, विशेष रूप से उच्च स्तरीय उपचारों के लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए केंद्रीकृत आपूर्ति केंद्र के रूप में कार्य करती हैं। भारत में 255 फार्मेशियां हैं और नवंबर 2025 तक इस नेटवर्क को पूरे देश में 500 आउटलेट तक विस्तारित करने का लक्ष्य है।

## विश्व की फार्मसी

भारत का मजबूत दवा क्षेत्र, जो मात्रा के हिसाब से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवा क्षेत्र है, ने इसे जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनने में सक्षम बनाया है, जो विश्व की कुल आपूर्ति का 20% प्रदान करता है। देश लगभग 200 देशों और क्षेत्रों को निर्यात करता है। भारत किफायती टीकों के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वैश्विक दक्षिण के लिए, भारत की दवा आपूर्ति- कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाली, आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। देश वर्तमान में वैश्विक एंटी-रेट्रोवायरल दवाओं का 70% से अधिक आपूर्ति करता है, जिससे जरूरतमंद देशों को किफायती दरों पर इन दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित होती है।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), भारतीय राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण (एनआरए) और संबद्ध संस्थानों को अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित कार्यात्मक टीका नियामक प्रणाली के संकेतकों को पूरा करने वाला पाया गया।

कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत ने कोवैक्सिन और कोविशील्ड सहित स्वदेशी टीके विकसित किए, जो अनुसंधान और बड़े पैमाने पर उत्पादन को एकीकृत करने की इसकी अनूठी क्षमता को दर्शाता है।

भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र लंबे समय से वैश्विक स्तर पर टीकों का आपूर्तिकर्ता रहा है, जो यूनिसेफ के 55-60% टीके उपलब्ध कराता है और डीपीटी, बीसीजी और खसरा टीकों की वैश्विक मांग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा करता है, जिससे दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी है।

भारत अब उच्च मूल्य वाले बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स और नवोन्मेषी चिकित्सीय दवाओं के निर्माण के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। भारत के जैव-अर्थव्यवस्था क्षेत्र में पिछले दशक में **13 गुना वृद्धि देखी गई है, जो 2014 में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 165.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है और 2030 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।**

केंद्रीय बजट 2026-27 में बायोफार्मा शक्ति परियोजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण, कार्यबल विकास, 1,000 से अधिक मान्यता प्राप्त नैदानिक परीक्षण स्थलों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की नियामक क्षमता में वृद्धि के माध्यम से बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के लिए भारत की संपूर्ण व्यवस्था को मजबूत करना है। बायोफार्मा में विशेषज्ञ मानव संसाधनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तीन नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) स्थापित किए जाएंगे और सात मौजूदा संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। यह पहल, मौजूदा राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के साथ मिलकर, अगली औद्योगिक क्रांति में भारत की वैश्विक भूमिका को गति प्रदान करने और भारत को एक वैश्विक जैव-विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखती है।

राष्ट्रीय जैवफार्मा मिशन (एनबीएम) - "इनोवेट इन इंडिया (आई3)" - ने 2017 में अपनी शुरुआत के बाद से ही अभूतपूर्व परिणाम हासिल किए हैं। विश्व बैंक द्वारा सह-वित्तपोषित और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) द्वारा कार्यान्वित, यह मिशन 150 से अधिक संगठनों से जुड़ी 101 परियोजनाओं का समर्थन करता है और 304 वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं सहित 1,000 से अधिक रोजगार सृजित कर चुका है। इस मिशन की उपलब्धियों में आयातित मशीनों की तुलना में बहुत कम लागत पर भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एमआरआई स्कैनर, टाइप 2 मधुमेह के लिए लिराग्लूटाइड का पहला बायोसिमिलर (आयातित संस्करण की लगभग एक तिहाई कीमत पर) और ज़ाइडस कैडिला द्वारा विकसित दुनिया का पहला डीएनए-आधारित कोविड-19 टीका, ज़ाइकोव-डी शामिल हैं। ये नवाचार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को अधिक किफायती बनाने की दिशा में भारत का योगदान हैं।

## स्वास्थ्य शिक्षा का विस्तार

चिकित्सा क्षेत्र में हो रही वृद्धि और सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए, भारत सरकार इस मांग को पूरा करने के लिए चिकित्सा शिक्षा का व्यवस्थित रूप से विस्तार कर रही है। पिछले 11 वर्षों में, भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब भारत में 23 सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित और अग्रणी अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (एआईएमएस) हैं, जिनमें असम के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थापित पहला एआईएमएस भी शामिल है। यहाँ 2,045 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 780 एलोपैथी, 323 दंत चिकित्सा और 942 आयुष संस्थान शामिल हैं। एमबीबीएस (बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी) के लिए चिकित्सा शिक्षा की सीटें 130% (51,348 से बढ़कर 118,190) और स्नातकोत्तर सीटों में 138% (31,185 से बढ़कर 74,306) की वृद्धि हुई है।

## निष्कर्ष

भारत का स्थानिक रोगों से जूझने वाले देश से वैश्विक चिकित्सा पर्यटन केंद्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के अग्रणी देश में बदलाव यह दर्शाता है कि रणनीतिक सरकारी हस्तक्षेप क्या हासिल कर सकता है। 180,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से लेकर 860 मिलियन से अधिक स्वास्थ्य आईडी वाले विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र तक निर्मित बुनियादी ढांचे ने न केवल देश में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार किया है, बल्कि भारत को विश्व स्तर पर गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवा के गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। जैसे-जैसे देश 2047 तक विकसित भारत के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, इसकी नींव मजबूती से रखी जा चुकी है: सुदृढ़

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, अत्याधुनिक डिजिटल व्यवस्था और यह सुनिश्चित करने की अटूट प्रतिबद्धता कि हर नागरिक को, चाहे वह किसी भी भौगोलिक स्थिति या आय का हो, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो, जिससे भारत विकासशील देशों में स्वास्थ्य समानता का एक आदर्श बन गया है।

## संदर्भ

- <https://www.who.int/campaigns/universal-health-coverage-day/2025>
- <https://knowindia.india.gov.in/profile/directive-principles-of-state-policy.php>
- chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mea.gov.in/images/pdf1/part4.pdf
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2222493&reg=3&lang=1>
- <https://scosta.gov.in/ministry-of-labor-and-employment-rsby/>
- <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care#:~:text=PHC%20addresses%20the%20broader%20determinants,feasible%20to%20people's%20everyday%20environment.>
- <https://aam.mohfw.gov.in/>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2224515&reg=3&lang=2>
- <https://dashboard.abdm.gov.in/abdm/>
- <https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=149066&reg=3&lang=2>
- <https://nhpr.abdm.gov.in/nhpr/v4/home>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2189415&reg=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2074630&reg=3&lang=2>
- <https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/yaws-eradication#:~:text=WHO%20certifies%20India%20as%20free,country%20as%20free%20of%20yaws>
- <https://www.pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=147093&reg=3&lang=2>
- <https://mohfw.gov.in/?q=en/pressrelease-102>
- Economic Survey 2025-26: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/Infographics%20English.pdf

- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2185049&reg=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2087878&reg=3&lang=2#:~:text=Both%2C%20Malaria%20cases%20and%20deaths,of%20India's%20malaria%20control%20efforts.>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2224451&reg=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2233632&reg=3&lang=1#:~:text=Cervical%20cancer%20remains%20the%20second,per%20the%20GLOBOCAN%202022%20data>
- <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer>
- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12702179/>
- <https://www.cdc.gov/cancer/hpv/basic-information.html>
- <https://www.gavi.org/news/media-room/gavi-and-government-india-establish-new-partnership-protect-millions-children-2026>

**पीआईबी शोध ईकाई**

**पीके/केसी/एनएस**